Amendment to National Highways Act

804. SHRI GHUFRAN AZAM Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state.

(a) whether Government propose to amend the National Highways Act,

(b) if so, the reasons therefor,

(c) whether it is a fact that the condition of National Highways throughout the country is in a very bad shape,

(d) if so, how much expenditure has been incurred by the Central Government to repair the National Highways during the past three years, year-wise, and

(e) what further steps Government propose to contemplate to maintain National Highways?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI MANUBHAI KOTADIA): (a) and (b) Yes, Sir. In order to mobilise additional resources

(c) and (d) National Highways in the country are generally in a traffic worthy condition and improvement works are undertaken keeping in view the existing condition, traffic intensity, inter-se priority on an All-India basis and availability of funds. Expenditure incurred on maintenance of various National Highways during the past three years is as under: —

1987-88	Rs	10,915 76	lacs
1988-89	Rs.	14,634 61	lacs
1989-90	Rs	15,796 29	lacs

(e) Introduction of computer-aided Pavement Management System for optimal utilisation of available scarce resources

नेपाल में पाकिस्तान समर्थक आतंकवादियों द्वारा अड्डे बनाये जाना

805. **श्री राम जेठमलानी :**
श्री बलराम सिंह यादव :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का ध्यान इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि कश्मीर के अनेक पकिस्तान समर्थक आतकवादी सगठन अपनी गतिविधिया चलाने के लिए नेपाल मे अपने अड्डे बना रहे है ,

(ख) यदि हा, तो क्या सरकार ने इस सबध मे नेपाल सरकार के साथ बात की है ;

(ग) क्या नेपाल मे इन अड्डों से निपटने के लिए सयुक्त कार्रवाई करने के सबध मे दोनों देशो मे कोई समझौता है ; और

(घ) यदि हा, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हा ।

(ख) से (घ) नेपाल और भारत की सरकारो के बीच समुचित स्तरो पर इसके संबध मे विचार-विमर्श होता रहा है । 25–26 नवम्बर, 1990 की हाल की अपनी नई दिल्ली की यात्रा के दौरान नेपाल के प्रधानमंत्री श्री कृष्ण प्रसाद भट्टाराई ने कहा था कि अगर नेपाल राज्य में किसी कश्मीरी अथवा पजाबी आतकवादी को शरण देने का कोई मामला उनकी जानकारी मे आता हैं तो वे सख्त कार्रवाई करेंगे । तथापि इस प्रकार के मामलों से संबद्ध कोई औपचारिक द्विपक्षीय समझौता नही है ।

फिजी में भारतीय मूल के लोगों के साथ भेदभाव

806. **श्री राम जेठमलानी :**
डा० जितेन्द्र कुमार जैन :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 जुलाई, 1990 के "द हिन्दू" से "रिटर्न टू द मदरलैंड" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है , यदि हां तो क्या यह सच है कि फिजी में भारतीय मूल के लोगों के साथ भेद भावपूर्ण और अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है ; और

(ख) क्या यह भी सच है कि इस व्यवहार के कारण फिजी के नागरिकों को फिजी छोड कर किसी अन्य देश में जाने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है ; यदि हा, तो चालू वर्ष में फिजी छोड कर जाने वाले लोगो की सख्या क्या है और क्या सरकार ने इस सबध मे कूटनीतिक कदम उठाए है, यदि हा, तो उनका ब्यौरा क्या है और उसका क्या परिणाम निकला है ?

विदेश मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) फिजी मे भारतीय मूल के लोगो के साथ जो जातीय भेदभाव का व्यावहार किया जा रहा है उसके प्रति तथा वहा की गैर-कानूनी सरकार द्वारा फिजी के नागरिकों के मानवाधिकारो का जो उल्लंघन हो रहा है उसकी भी भारत सरकार की जानकारी है । इसकी वजह से पिछले तीन साल मे करीब 21,000 लोग वहाँ से विदेशों मे चले गए है, लेकिन बताया जाता है कि कुछ लोग लौट भी आए है । वर्ष 1990-91 के ठीक-ठीक आकडे उपलब्ध नही है । भारत सरकार ने कई अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर फिजी मे जातीय भेदभाव तथा मानव-अधिकारो के उल्लघन का सवाल उठाया है। सम्बद्ध देशों के साथ द्विपक्षीय बैठको में भी इस संबंध में विचार-विमर्श हुआ है । भारत सरकार जातीय भेद-भाव का तथा फिजी मे मानवाधिकारो के उल्लघन का विरोध करने वाले सभी फिजी वासियो को राजनयिक और नैतिक समर्थन दे रही है । फिजी की स्थिति के प्रति अन्तर-राष्ट्रीय जागरुकता यद्यपि बढ रही है लेकिन अन्य कुछ ही ऐसी सरकारे है जिन्होने गैर-कानूनी सरकार की जातीय भेद-भाव की नीति का सक्रिय विरोध किया है ।

गंगा कार्य योजना

807. **श्री बलराम सिंह यादव :**
डा० जितेन्द्र कुमार जैन :

क्या पर्यावरण और वन मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में गंगा कार्य योजना के अधीन शुरू की गई परियोजनाओ पर काम लगभग रोक दिया गया है ;

(ख) यदि हा, तो सरकार ने उत्तर प्रदेश मे इस योजना पर कितना धन व्यय किया है ,

(ग) व्यय किए गए धन मे इस योजना के अतर्गत कितना काम किया गया है , और

(घ) इस कार्य योजना को अधूरा छोडने के क्या कारण है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, नही । उत्तर प्रदेश मे परियोजना की स्कीमो पर कार्य रूका नही है । सस्वीकृत की गई 107 स्कीमो में मे 66 स्कीमे पहले ही पूरी की जा चुकी है । शेष स्कीमे कार्य पूरा होने के विभिन्न चरणो मे है ।

(ख) दिनाक 31-10-90 तक 77.6 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की जा चुकी है ।

(ग) हरिद्वार-ऋषिकेश मे 16 स्कीमें, फतेहगढ़ फर्रुखाबाद मे 3 स्कीमो, कानपुर मे 7 स्कीमो, इलाहबाद मे 13 स्कीमें, बिजनौर में 2 स्कीमे और वाराणसी में 25 स्कीमें पर क्रमश 11 05 करोड रुपये, 1 02 करोड रुपये, 12 45 करोड रुपये, 3 93 करोड रुपए, 2 90 करोड रुपये और 35 91 करोड रुपये खर्च किए जा चुके हैं , शेष कार्य प्रगति पर है ।

(घ) प्रश्न नही उठता ।

Financial assistance to Paradeep Port Trust

808. **SHRI KAHNU CHARAN LENKA** Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state

(a) whether any proposal has been received from the Paradeep Port Trust for providing adequate financial assistance for the improvement of the existing iron-ore berths and ore handling plant at that port; and